[श्रीमती ऊषा वर्मा]

अस्त-व्यस्त हो जाते हैं । क्षेत्र में जितने ग्रामीण पी० सी० ओ० खोले गए हैं उनकी लाइनें दो-दो साल से टूटी पड़ी हैं जिनकी अभी तक कोई मरम्मत होती नहीं दीखती है तथा यह भी ज्ञात हुआ है कि पी० सी० ओ० के बोर्डों को अटेण्ड करने के लिए स्टाफ ही नहीं है जिससे यह सब पी० सी० ओ० बेकार पड़े हुए हैं जिन पर सरकार का काफी धन खर्च हो चुका है । अतः विभाग को शीघ्र इस ओर ध्यान देकर उपरोक्त त्रुटियों को ठीक कराया जावे ।

(ii) DEMAND FOR CONSTRUCTION OF PROPOSED TALCHAR-SAMBALPUR RAIL LINK.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack) : The absence of the proposed 160 kms. Talcher-Sambalpur rail link has affected Orissa's economic development. The western districts of Orissa, which include Sambalpur, Balangir, Kalahandi and Sundergarh, possess large mineral reserves of coal, limestone, bauxite and china clay ; and have a rich forest and agricultural belt. But due to lack of direct rail link, movement of both mineral and agricultural goods is difficult. The State Government has appealed to the Union Government to give priority for the construction of this rail link. But it is regrettable that Union Government has not taken any effective measures in this connection. Though the Ministry of Railways has surveyed the proposed scheme twice, the survey report did not make full and judicious evaluation of the economic prospect of this rail link and its load factor. A new line connecting Talcher and Sambalpur will reduce the distance from Cuttack and Bhubaneswar to Delhi substantially, and at the same time relieve congestion on saturated sectors between Cuttack and Kharagpur to Tata Nagar which are ,at present heavily worked lines. This rail link will serve as a link between coastal and western districts of Orissa, and expand the hinterland of Paradip right upto Raipur and Bhilai. The traffic projection is heavy, as the steel plant and fertilizer plants are coming up at Daitari and Paradip of Orissa respectively. This project will draw lime stone, dolomite and other minerals from Katni and Satna areas of Madhya Pradesh, and Biramitrapur of Sundergarh district of Orissa ; and the goods traffic is expected to be of the order of more than one million tonnes. The railway survey committee have not taken into consideration the industrial development of the State, to project the traffic position properly. I, therefore, urge the Government to suggest to the railway committee, which is again undertaking the survey at present, to take the above matter into consideration. I demand that the proposed Talcher-Sambalpur rail link should be included for construction in the Sixth Plan.

(iii) DELAY IN SETTING UP OF PETRO-CHEMICAL PROJECT IN BIHAR.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, 1980 में लोक सभा में एक गैर सरकारी प्रस्ताव आया कि बरौनी (बिहार) में पैट्रो-केमिकल कम्पलेक्स की स्थापना की जाये । सदन की भावना को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन पैट्रोलियम मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा और कालबद्ध योजना के अन्तर्गत बरौनी में पैट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । समिति का प्रतिवेदन भी भारत सरकार को प्राप्त हो चुका है जिसने इस बात की सिफारिश की है कि बरौनी में पैट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स की स्थापना की जाये । उसके पश्चात् 1981 में पैट्रोलियम की मांग के बाद विवाद के उत्तर में तत्कालीन मंत्री ने आश्वासन ही नहीं दिया

बल्कि घोषणा की कि एक बहुत बड़ा पैट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स का प्रोजेक्ट बिहार में होगा। स्थान चयन बाद में होगा। 1980 से बिहार के संसद सदस्यगण एवं बिहार सरकार से बार-बार इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये स्मारक-पत्र द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से अनुरोध करती आ रही है। परन्तु अभी 1982 के वर्ष का आधा से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी इस योजना के लिये न तो योजना में राशि आवंटित की गई है और न कोई ठोस कार्यवाही ही की जा रही है। इस योजना के अति विलम्ब एवं भारत सरकार की उदासीनता के कारण बरौनी, बेगूसराय एवं बिहार की जनता में क्षोभ व्याप्त है। अतः सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले।

(iv) ADEQUATE COMPENSATION BY D.D.A. TO LAND OWNER ON ACQUISITION OF THEIR LAND

श्री राम विलास पासवान (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकहित से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—डी. डी. ए. की घोषणा एवं नियमों के अनुसार जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जाती है उन किसानों को अधिग्रहीत भूमि के बदले रोजगार तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में आवासीय प्लाट तथा कमर्शियल प्लाट दिया जाता है। डी. डी. ए. ने कमर्शियल प्लाट देना बिल्कुल बंद कर दिया है और यही हालत रोजगार की भी है।

रिहायशी प्लाट जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन यह नो प्राफिट नो लास पर कतई आधारित नहीं हैं। किसानों को मुआवजा 75 पैसे प्रति वर्गगज से लेकर 5 या 7 रुपये प्रति वर्गगज विकास पर करीब 70 रुपये जोड़ कर दिया जाता था। यह राशि 1980 तक 75 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से दी गई। उन्हीं विकसित कालोनियों में 1980 में 192 रुपये प्रति वर्ग मीटर वसूल किया गया अब 1982 में इसकी दर एकाएक 358 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुँच गई है जो सर्वथा अनैतिक एवं असंवैधानिक है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है।

किसानों की जमीन की कीमत 3 रुपये प्रति वर्ग गज और उसी को 358 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राधिकरण द्वारा बेचा जा रहा है।

अतः सरकार से मांग है कि पुरानी विकसित दर 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ही किसानों को प्लाट दिए जाएं।

(v) ALLEGED DENIAL OF ADMISSION BY DELHI UNIVERSITY TO STUDENTS OF BIHAR IN VIEW OF 10+2+3 SYSTEM.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार उड़ीसा, आसाम के छात्र सैकड़ों की संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं पर उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वे परेशान हैं कि क्या करें।

बिहार के छात्रों ने बतलाया है कि केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही है, जिन लोगों ने 10+2+3 की परीक्षा पास की है। बिहार में इस प्रकार की पढ़ाई अभी-अभी शुरू हुई है। अतः वहां के पहले के छात्र 10+2+3 की परीक्षा पास नहीं कर सकते थे। इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार की शर्त लागू कर बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि के छात्रों के साथ भारी अन्याय किया है। इस नीति के फलस्वरूप बिहार के अच्छे